International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 7, July - 2019
प्ैैछ;वद्धरू 2249.7382 द्य प्उचंबज थ्ंबजवतरू 6.939 द्य

International Journal of Research in Economics and Social Science (IJRESS)
Email:- editorijrim@gmail.com, http://www.euroasiapub.org (An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

42

आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के बाद की अवधि की विकास घटनाएँ

डॉण्कंचन
एमए(राजनीतितिज्ञान)
पी.एच.-डी(राजनीतितिज्ञान)
पटनातिश्वतिद्यालयपटना

आर्थिक सुधारों का क्रियान्वयन किये हुए 3 दशकों से थोड़ा अधिक समय हो चुकाहै। भारतीय अर्थव्यवस्था में इस अवधि में हुए वृहत् प्रगतियों का मूल्यांकन करने केलिए यह मामूली अवधि है। इस अवधि में किये गये सुधारों की एक संक्षिप्त रूपरेखाप्रस्तुत करने के पश्चात् हम सुधार नीति के आलोचनात्मक मूल्यांकन का प्रयास करेंगे।क्योंकि इन सुधारों ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया है। इन उपायोंमें से अधिकांश सुधार कार्यक्रम के प्रारंभिक चरण में किये गये थे, किन्तु हम संपूर्णसुधार काय Zक्रमों को पूर्ण नहीं कर सके।

1) उपायों की उचित क्रमबद्धता, सभी क्षेत्रों में पूरक सुधार (उदाहरण के लिए

साथ सुधारों के प्रति दृष्टिकोण सतर्कतापूर्ण रहा है।

2) उदारीकरण की गति एवं क्रमबद्धता घरेलू प्रगतियों विशेष रूप से मौद्रिक एवं

3) सुधारों के प्रति दृष्टिकोण ’धूम.धड़ाके’ के स्थान पर धीमा एवं सतत् रहा है।

साथअपेक्षाकृत अधिक वृद्धि तथा कार्यकुशलता पर था।

श् ाोधकर्ता सुधारों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए भिन्न.भिन्न प्रविधियों का उपयोग

करते हैं। इस संबंध में सामान्यतः दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं-

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 7, July - 2019
प्ैैछ;वद्धरू 2249.7382 द्य प्उचंबज थ्ंबजवतरू 6.939 द्य

International Journal of Research in Economics and Social Science (IJRESS)
Email:- editorijrim@gmail.com, http://www.euroasiapub.org (An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

43

1) माडल आधारित तथ्य विरोधी अनुकरण जो वैकल्पिक सुधार परिवेश क े अंतर्गतवास्तविक परिणामों की तुलना करने का प्रयास करते हैं।

2) ’पूर्व एवं पश्चात्’ दृष्टिकोणहम सुधारों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए पश्चात्वर्ती दृष्टिकोण कामूल्यांकन करेंगे।

आर्थिक सुधारों की उपलब्धि के विषय में कम से कम यह कहा जा सकता है सुधारोंने अर्थव्यवस्था को 1990.91 के गंभीर दिल के दौरे से बचा लिया। किन्तु यह सबकुछ नहीं है। वर्तमान आर्थिक स्थिति जून 1991 की तुलना में परिवर्तित हो गयी है।

नये आर्थिक वातावरण में स्वयं शब्दावली ही परिवर्तित हो गयी है। इससे पूव Z तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा शक्ति, कार्यकुशलता, लाभनीयता,
तकनीकसुधार, विदेशी पूँजी, वैश्वीकरण तथा सुनहरा हस्तमिलन इत्यादि हैं। आइये, हम बड़ ेपरिवर्तनों में से कुछ का पुनरावलोकन करें।

यह अंकित करना हर्ष का विषय है कि पिछले दो दशकों से बाह्य क्षेत्र के प्रबंधनकी विशेषता ’बाह्योन्मुखी’, विनियोग, उदारीकरण तथा रुपय े की परिवर्तनीयता के मामलेम ें सतर्कता के विवेकपूर्ण संयोग के रूप में है। इसका प्रमुख परिणाम यह रहा है

आर्थिक सुधारोत्तरअवधि में बृहत्विकास घटनाकि जिन अत्यधिक उतार.चढ़ावों ने संपूर्ण विश्व में करेंसी बाजारों को अस्तव्यस्त करदिया था, उनका भारत पर बहुत कम विनाशकारी प्रभाव पड़ा।

कुछ अन्य सकारात्मक लाभों की गणना निम्न प्रकार की जा सकती है:

1) हमारे निर्यात कार्य निष्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि इस सोच को और मज़बूत बनादेती है कि ’भारत में निर्मित’ की धारणा धीर.े धीरे किन्तु निश्चित रूप से अपनेरूप में आ रही है। उपलब्ध आँकड़े यह व्यक्त करते हैं कि निजी निगमित क्षेत्रकी निर्यात गहनता (प्रति इकाई बिक्री पर विनिर्माण निर्यात) 1998.99 में 13.37प्रतिशत से दोगुनी होकर 2008.09 में 24.23 प्रतिशत हो गयी है। इसके अतिरिक्त50 बड़े व्यावसायिक घरानों, विदेशी स्वामित्व वाली एवं सरकारी कंपनियांे के निर्यातबिक्रीअनुपात में भी इस अवधि में सुधार हो गया है। इसक े अतिरिक्त निगमोंके विनियोग में भी इस अवधि में सुधार हो गया है। इसके अतिरिक्त निगमोंके विनियोग पर प्रतिफल घरेलू बाज़ारों की अपेक्षा बिक्री पर अधिक आता है।यह स्थिति पूर्व.उदारीकरण तथा उदारीकरण के प्रारंभिक दिनों की अवधि की तुलनामें बिलकुल विपरीत है जहाँ कि लाभों में कम अंतर ने संरक्षित घरेलू बाज़ारमें बिक्री को अत्यधिक आकर्षक प्रस्ताव बना दिया था।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 7, July - 2019
प्ैैछ;वद्धरू 2249.7382 द्य प्उचंबज थ्ंबजवतरू 6.939 द्य

International Journal of Research in Economics and Social Science (IJRESS)
Email:- editorijrim@gmail.com, http://www.euroasiapub.org (An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

44

2) हमारे निर्यातों की उत्पाद संरचना में तकनीक गहन तथा उच्च मूल्य उत्पादों
कीओर धीमी गति से किंतु निर्णायक रूपांतरण हो रहा है। यह स्वचालित वाहनोंके निर्यातों म ें तीव्र वृद्धि से सूचित होता है जिसका निर्यात वर्तमान दशक मेंसॉफ्टवेयर निर्यातों से भी अधिक हो गया है। इससे ’उच्च बाजार’ एव ं ’आला’स्थानों में भारत का प्रवेश संभव हो गया है।

3) निर्यातों की प्रति इकाई आयात के रूप में मापित निगमित निर्यातों की आयातगहनता 1998.99 में 114.35 प्रतिशत से कम होकर 2008.09 में 86.86 प्रतिशतहो गयी जो इस बात को व्यक्त करती है कि आयातों के उपयोग में कंपनियाँअधिक मितव्ययी हो रही हंै। वास्तव में, निगम नये मिलेनियम के प्रथम दशकसे आयातित उत्पादों में अधिक मूल्य वृद्धि कर रहे हैं। यह कुल कच्चा मालव्ययों में आयातित कच्चे माल के अनुपात तथा 1998.99 एवं 2008.09 के बीचइकाई सकल स्थिर परिसंपत्तियों पर पूँजीगत वस्तुओं के आयात में वृद्धि के बावजूदहै।

4) अन्य बड़ा आश्चर्य यह है कि पहले से हटकर निगम देश के विशुद्ध विदेशीविनिमय
अर्जित करने वालों के रूप में उभर कर आ रहे हैं। निजी क्षेत्र काविशुद्ध विदेशी विनिमय प्रवेश की दर 1998.99 में ()14.35 प्रतिशत से परिवर्तितहोकर 2008.09 में ($) 13.14हो गयी है। यह परिवर्तन उच्चस्थ 50 व्यावसायिकघरानों में और अधिक स्पष्ट है जहाँ ये संख्याएँ 41.3 से बढ़कर उपरोक्त अवधिमें ही $17.5 हो गयी है। यह सब इस बात का संकेत करता है कि निगमनिर्यात बाजार में सरकार द्वारा दिये जाने वाले प्रोत्साहनों के कारण नहीं बल्किनिर्यातों से कार्यकुशलता में लाभ की संभावनाआंे के कारण प्रवेश कर रहे हैं।

5) विनिमय की ’हवाला दर’ लगभग गायब हो गयी है। जो विदेशी विनिमय भंडारजून 1991 में कम होकर $1 बिलियन से कम हो गये थे, वे अब $300 बिलियनसे अधिक हो गय े हैं। पिछले बीस वर्षों (1991.92 एवं 2011.12 के बीच) में विदेशीप्रत्यक्ष विनियोगांे की स्वीकृति $100 बिलियन पार कर गयी है। इसकी तुलना1980 के दशक की अवधि में किसी एक वर्ष में अधिकतम $20 मिलियन से कीजा सकती है। विदेशी संस्थागत विनियोग प्रारंभ में बाल्टी भर कर अर्थात् अत्यधिकआया। 1993.2009 की अवधि में ही इनका अनुमान $40 बिलियन है। इसकीतुलना पूर्व वर्षों में शून्य के परिप्रेक्ष्य में की जा सकती है।

6) केवल 7 वर्ष पूर्व 5 से कम की तुलना में 9000 श्रृंखला से सर्टिफिकेट प्राप्तकरके अंतर्राष्ट्रीय गुण

7) विदेशी विनियोग अब एकतरफा मार्ग नहीं है। निगमित भारत अब संयुक्त उपक्रमों,अधिग्रहणों एवं लाइसेंस व्यवस्था के माध्यम से संपूर्ण विश्व में जाने लगा है।अनेक तत्वों ने इस प्रक्रिया को सुविध्

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 7, July - 2019
प्ैैछ;वद्धरू 2249.7382 द्य प्उचंबज थ्ंबजवतरू 6.939 द्य

International Journal of Research in Economics and Social Science (IJRESS)
Email:- editorijrim@gmail.com, http://www.euroasiapub.org
;।द वचमद ंबबमेे ेबीवसंतसलए चममत.तमअपमूमकए पदजमतकपेबपचसपदंतलए उवदजीसलए ंदक निससल तममितममक रवनतदंसण्द्ध

45

दरें, आर्थिक चक्र के उच्चतम स्तर में मजबूतघरेलू वृद्धि द्वारा वैश्विक विस्तार के लिए आवश्यक नकदी का सृजन इत्यादि।बाहर की ओर प्रवाह $15 बिलियन वार्षिक से अधिक हो गया। अभी भारतीयबहुराष्ट्रीय निगम कहना बहुत जल्दबाजी होगी, किन्तु वे ऐसे क्षितिज पर है जिसेवैश्विक भारतीय अधिग्रहण में प्रथम विश्राम स्थल कहा जा सकता है।

.देनयोजना में चुनाहै जो
संकटग्रस्त देशों का बचाव करती है। अतः अब हम उधार लेनेवाले के बजाय उधार देने वाले बन गये हैं।बाह्य क्षेत्र में उपलब्धियाँ अधिक प्रशंसनीय प्रतीत होती हैं। संभवतः इसका कारणकिये गये उपायों की संगति, एक साथ कार्यवाही एवं दूरदर्शिता थी। उदाहरणके लिए, अब सभी व्यापार समान भुगतान शासन प्रणाली के अंतर्गत हंै (अब कोईकठोर, कोमल तथा रुपये में व्यापार क्षेत्र नहीं है)। एकीकृत विनिमय दर चालूखाते में रुपये की परिवर्तनीयता के वास्तविक मूल्य को अधिक प्रतिबिंबित करतीहै। अधिकांश आयातों तथा निर्यातों पर प्रतिबंधों की समाप्ति, आयात करों कीअत्यधिक कमी, सोने एवं चाँदी का उदार आयात कुछ अन्य उपाय थे। पहलेकी पुरानी, भद्दी, पुनः पूर्ति तथा अग्रिम लाइसेंस, नकद क्षतिपूर्ति तथा अनुदानयोजनाओं के बजाय अब कर छूट के साथ स्पष्ट निर्यात प्रोत्साहन प्रणाली विद्यमानहंै। विदेशी विनियोगों पर प्रतिबंधों की लगभग पूर्ण समाप्ति बाह्य क्षेत्र में नईआर्थिक नीतियों का एक सकारात्मक लक्षण हो गया है। ये परिवर्तन आधारभूतहुए हैं।

यह भी तर्क दिया जाता है कि बाह्य मोर्चे पर अर्थव्यवस्था के दोष अधिकाधिक स्पष्टहोते जा रहे हैं।यह तर्क दिया जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण एक चूहे को हाथियोंके झुंड में मिला देने जैसा है।

1) निम्नलिखित कारण निर्यात मोर्चे की उपलब्धियों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं:

- ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि निर्यातों में कोई ऐसा मेदन हुआ है जो विश्वनिर्यातों में देश के अंश में वृद्धि के रूप में प्रतिबिंबित होगा। इसका दोदृष्टिकोणों से और अधिक आलोचनात्मक अवलोकन किया जाना चाहिए। (क)निर्यातों की संरचना में संभवतः कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। (ख) निगमितक्षेत्र का कार्य निष्पादन निर्यातों की तीव्रता में वृद्धि करने का कोई प्रमाणप्रस्तुत नहीं करता है।

जैसे - सिल.े सिलाए वस्त्र, चमड़े से निर्मित वस्तुएँ

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 7, July - 2019
प्ैैछ;वद्धरू 2249.7382 द्य प्उचंबज थ्ंबजवतरू 6.939 द्य

International Journal of Research in Economics and Social Science (IJRESS)
Email:- editorijrim@gmail.com, http://www.euroasiapub.org (An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

46

- निर्यातों के परिप्रेक्ष्य में अनेक मोर्चो पर सुधार अपूर्ण रहे हैं। इसके अंतर्गतभेदभावपूर्ण उत्पाद शुल्क संरचना, निर्यातों एवं आयात गतिविधियों का बोझिलतरीका, श्रम बाजार के सुधार तथा घटिया बैंकिंग एवं बीमा सेवाएँ इत्यादिसम्मिलित हैं।

2) सुधार के पश्चात् की अवधि में भारत की बाह्य देयताओं में तीव्र वृद्धि हुइ Z है।पिछले दशक मे ं विदेशी विनिमय भंडार में वृहत वृद्धि अंतिम विश्लेषण में पर्याप्तसिद्ध नहीं होती हंै।इसके अतिरिक्त तेज़ी से बढ़ते हुए भंडार ऐसे चिह्न हंै जिन्हें कभी डेनमार्क कीबीमारी (किन्तु अब 1997 के बाद जिसका नाम ’थाई बीमारी’) के रूप में पुकाराजाता था। यह वृद्धि चालू खाते में नहीं हुई है बल्कि पूँजीगत खाते में हुई हैजिसमें गर्म से बहुत गर्म मुद्रा सम्मिलित है जो बहुत अल्प सूचना पर देश कोछोड़ सकती है।

3) विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग सामान्यतः एक ऐसा विनियोग माना जाता है जोभौतिक
ेष रूप से प्रबंधकीय निपुणताके कारण स्थिरता
के अंश से संबंधित है। तथापि, निजी सममूल्य अंश कोषोंएवं जोखिम पूँजी कोषों के माध्यम से नये प्रकार के थ्क्प्
उतार.चढ़ाव की संभावनानिहित होती है।

4) इसी प्रकार समता पूँजी में वर्तमान भागीदार प्राप्त करने या भारतीय कंपनियों मेंविदेशी भागीदारी में विस्तार करने को थ्क्प् के रूप में वर्गीकरण किया जाता है।किन्तु वे

5) विदेशी संस्थागत निवेष अपने खाते में सामान्यतः दीर्घकालीन निवेशक होतेहैं तथा उनकी प्रबंधकीय नियंत्रण में बहुत कम या कोई रुचि नहीं होती है।तथापि, भारत मेंश्रेणी में

विशेष रूप से पोर्टफोलियो प्रवाहसरलतापूर्वक अपनी दिशा परिवर्तित कर सकते हैं तथा इस प्रकार पूँजी प्रवाहके संबंध में ’मूल के नियमों’ को लागू करना कठिन होता है।

6) भारत ने विदेशी सहयोग तथा थ्क्प् के माध्यम से आयातित तकनीक डिज़ाइनएवं उपकरणों पर अत्यधिक विश्वास किया तथा स्वदेशी क्षमता का सृजन करनेपर बहुत कम

सीमा को गंभीर रूप से कम करता है जो देश मेंन्याय एवं सतत्ता से संगत अपनी विकास प्राथमिकताओं का निर्माण करने मेंहो सकती है।

7) ज्यो ं.ज्यों निजी सममूल्य एवं हेज कोष विनियोगों में वृद्धि होती है, अंशधारकोंकी सक्रियता अधिक स्पष्ट हो जाती है। पहले से ही विदेशी निवेशक की माँगकी शर्तों के चिह्न

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 7, July - 2019
प्ैैछ;वद्धरू 2249.7382 द्य प्उचंबज थ्ंबजवतरू 6.939 द्य

International Journal of Research in Economics and Social Science (IJRESS)
Email:- editorijrim@gmail.com, http://www.euroasiapub.org (An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

47

हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था को चोट पहुँचा सकते हैं। व्यष्टिस्तर पर वे उस व्यवस्था के विषय में आग्रह करते हैं जो उद्योग की अपेक्षास्थानीय माँगांे का अपेक्षाकृत अधिक हिस्सा प्राप्त करने में उन्हें सक्षम बनाते हैं।समष्टि स्तर पर पहले से ही भारत पर आयातों को और अधिक उदार बनानेका दबाव है। अब तक भुगतान संतुलन विपरीत होने के तर्कके आधार पर भारत के पासएक बड़ी संख्या में मदों पर तटकर लगाने काविकल्प था। उन विदेशी निवेशकों का प्रतिनिधित्व करने वाले देशों की ओर सेभारत पर इस छूट को त्याग देने का दबाव है।

8) वैश्वीकरण की अवधि के बाद सेवा क्षेत्र को होने वाली कुल आय का लगभग1/3
भाग आय विदेशी नागरिकों को हुई है। इसकी विपरीत प्रक्रिया अर्थात् वैश्विकआय का अंश प्राप्त करने की प्रक्रिया आनुपातिक रूप से बहुत कम रही है।अन्य शब्दों में, हमने अपनी अर्थव्यवस्था में खाने हेतु विदेशियों के लिए अवसरखोले हैं। कुल मिलाकर हमें विदेशी अंतःक्षेत्र की और अधिक किलेबन्दी दिखायीदेती है जो पहले से ही हमारे पास एक छोटी, आधुनिक एवं तकनीकी रूप सेउन्नत अर्थव्यवस्था है जो बाहरी विश्व से अधिक तथा भारत से अपेक्षाकृत कमजुड़ी हुई है। किन्तु, इस प्रकार की विदेशी अंतःक्षेत्र अर्थव्यवस्था बनाये रखने योग्यनहीं है। कालांतर में इस विदेशी अंतःक्षेत्र की दीवार को बाहर वालों द्वारा पारकर लिया जायेगा या इसकी नींव सामाजिक मुठभेड़ द्वारा खोखली कर दी जायेगी।

9) भारत को एक नयी वृद्धि के मार्ग पर स्थापित करने वाली पूँजी के आगमन कीभूमिका उन कारणों से विकास प्रक्रिया कमज़ोर बना देती है जो हाल के समयमें स्पष्ट हो गये हैं। इस कमज़ोरी का एक स्रोत त्ठप् द्वारा रुपये के विनिमयदर में वृद्धि को रोकने के प्रयासों के बावजूद उसमें निरंतर वृद्धि थी। रुपये केमूल्य में वृद्धि भारतीय निर्यातों की प्रतिस्पर्धा शक्ति को कम कर रहा था तथाउस निर्यात प्रोत्साहन को कमजोर बना रहा था जिसने सेवा एवं विनिर्माण दोनोंके सुधार में योगदान किया। कमज़ोरी का अन्य संभव स्रोत विदेशी पूँजी केबहिर्गमन के कारण तरलता संकुचन का डर है जिसके कारण भारत के आर्थिककार्य निष्पादन से संबंधित नहीं हंै। विदेशी पूँजी प्रवाह की निर्भरता ने भारत कोअन्य

आय को स्वदेश ले जाते हैं ताकि अन्य स्थानोंपर बचत पूरी की जा सके एवं नुकसान की भरपाई की जा सके।

10) यद्यपि देश में लगायी गयी अस्थिर पूँजी का बाज़ार मूल्य अनिश्चित होता है,भारत

संभावना है। यहाँ तक कि यदि अधिकारी रूढ़िवादी राजकोषीयएव ं मौद्रिक नीति अपनाते हैं तो भी देश को भुगतान संतुलन संकट कासामना कर पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 7, July - 2019
प्ैैछ;वद्धरू 2249.7382 द्य प्उचंबज थ्ंबजवतरू 6.939 द्य

International Journal of Research in Economics and Social Science (IJRESS)
Email:- editorijrim@gmail.com, http://www.euroasiapub.org (An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

48

अत्यधिक अस्थिर एवं प्रमुख रूपसे थ्प्प् द्वारा लाभ प्राप्त करने के कारण विदेशी विनिमय की निकासी वर्तमान मेंभारत को देखते हुए बहुत अधिक है। जो उपनिवेशवादी युग के बादके भाग की अवधि में अंग्रेजों द्वारा शुल्क वसूल किये जाने से तुलना करने कोप्रेरित करता है।

इस अवधि में निगमित पुनर्संरचना, लागत विवेकीकरण, उत्पादकता सुधार, क्षमता कीबाधाआंे में कमी के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा उल्लेखनीय सफलता प्राप्तकी गयी है। खेत से गैर.खेत, ग्रामीण से शहरी, एनालाग से डिज़िटल, शारीरिक सेतकनीक द्वारा संचालित, घरेलू ध्यान से निर्यात जैसे अनेक संक्रमण एक साथ हो रहेहंै। सकारात्मक उपलब्धियों में से कुछ को निम्न प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जारहा है:

1) 1990 के दशक तथा 2001.10 की अवधि में 6.9 प्रतिशतवृद्धि की दर कीप्रवृत्ति 1980 के दशक में दर्ज की गयी 5.5 प्रतिशत की अपेक्षा स्पष्ट रूप सेअधिक है। औसत वृद्धि दर के रूप में 1990 के दशक मे ं 6.5 प्रतिशत तथा2002.10 की अवधि में 8 प्रतिशत, 1980 के दशक में 5.8 प्रतिशत की अपेक्षाबेहतर थी।

2) घरेलू विनिर्माण क्षेत्र ने आयात प्रतिस्पर्धा एवं बदलती हुई समष्टिपरक दशाओं केप्रत्युत्तर में अपने सापेक्षिक लाभ की पुनः खोज करने तथा उत्पादन क्षमताओं केपुनः निर्माण करने में उल्लेखनीय लचीलापन, योग्यता एवं प्रवीणता प्रदर्शित कीहै। देश विनिर्माण क्षेत्र को महत्त्वपूर्ण क्षमता एवं तकनीक को उन्नत करने केचरण में देख रहा है। यह स्वदेश म ें विनियोग माँग का सृजन कर रहा है।तथा साथ ही घरेलू फर्मों को विदेशी बाजारों में उच्च कोटि की तकनीकों की

तलाश में उनकी गति तीव्र कर रहा है।उत्पादकता में तीव्र गति से वृद्धि हुर्ह हैं। इसका अथ Z कम श्रमिकों द्वारा अधिकउत्पादन दिये जाने से होता है। उत्पादकता में तीव्र वृद्धि तकनीक म ें प्रगति,प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन तथा माँग करने वाले नियोक्ताओं एवं चुनाव करने वालेउपभोक्ताओं को संतुष्ट करने की आवश्यकता से उत्पन्न होती है। मज़दूरी मेंवृद्धि की बढ़ी हुई उत्पादकता का कारण एवं प्रभाव दोनों ही के रूप में देखाजा सकता है। फिर भी भारत को विकसित पश्चिम देशों में स्वीकार की गयीप्रक्रियाओं एवं प्रणाली के साथ आने में अभी बहुत लंबा मार्ग तय करना है।

3) 1983 से 1993.94 की अवधि में 2.6 प्रतिशत से 1993.94 से 1999.2000 की अवधिमें 1.2 प्रतिशत की रोज़गार वृद्धि दर में प्रारंभिक गिरावट के पश्चात् यह 2000.01 से 2004.05 की अवधि में तेज़ी से बढ़ कर 3.8 प्रतिशत हो गयी। यह दरजनसंख्या वृद्धि की दर की अपेक्षा दुगुनी से अधिक है। इसके अतिरिक्त ग्रामीणएवं शहरी भारत दोनों में वास्तविक मज़दूरी की दरों में वृद्धि हो रही है।उदारीकरण के पश्चात् की अवधि में (1993.94 से 2004.

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 7, July - 2019
प्ैैछ;वद्धरू 2249.7382 द्य प्उचंबज थ्ंबजवतरू 6.939 द्य

International Journal of Research in Economics and Social Science (IJRESS)
Email:- editorijrim@gmail.com, http://www.euroasiapub.org (An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

49

05) में वास्तविक मज़दूरीवृद्धि उदारीकरण से पूर्व (1983.1993.94) की अवधि की अपेक्षा अधिक तेज़ी सेहुई है। यह प्रवृत्ति उसके बाद भी निरंतर बनी रही है। इस वृद्धि स े ग्रामीण,शहरी, नियमित एवं आकस्मिक सभी श्रेणियों को लाभ मिला है। तथापि, नियमितश्रमिकों की स्थिति आकस्मिक श्रमिकों से थोड़ी बेहतर थी तथा ग्रामीण श्रमिकोंकी स्थिति शहरी श्रमिकों से बेहतर थी। नियमित एवं आकस्मिक श्रमिकों के बीचमज़दूरी के अंतर ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में बढ़ते रहे हैं। यह ग्रामीणक्षेत्रों के नियमित एवं आकस्मिक के बीच कम हुआ है।

4) निगमित क्षेत्र के परिणाम यह प्रदर्शित करते हैं कि यद्यपि विशुद्ध लाभ में वृद्धिहुई
है किन्तु सकल लाभ सीमाएँ कम होती रही हैं। जिसका अर्थ होता है किउपभोक्ता अधिक लाभान्वित हो रहे हैं। अतः हम ’विजयी’ की स्थिति में हैं जिसमेंउत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों को ही लाभ हुआ है। यही लाइसेंस विहीन उत्पादनतथा उदारीकृत आयातों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के माध्यमसे सुधारों को प्राप्त करना चाहिए।

5) अब वृद्धि की प्रेरणाएँ संपूर्ण अर्थव्यवस्था में विस्तृत रूप से वितरित हैं। अर्थव्यवस्थाके सभी क्षेत्र ’वृद्धि के सुर’ का अनुभव कर रहे हैं। एक पर्यवेक्षक इस प्रकारप्रस्तुत करता है ’कल्पना से फैशन तक सब कुछ चलायमान है।’

6) उदारीकृत शासन प्रणाली के अंतर्गत भारतीय व्यापार चक्र नियंत्रित शासन प्रणालीके अंतर्गत की अपेक्षा बहुत कम अस्थिर है। उदारीकरण ने आर्थिक अभिकर्ताओंके लिए जोखिम में हिस्सेदारी के वातावरण का सृजन किया है। यद्यपि आर्थिकखुलेपन के पश्चात् अर्थव्यवस्था बाह्य धक्कों से अपेक्षाकृत अधिक दोषपूर्ण हो गयीहै किंतु उदारीकरण की स्थिति में उत्पादन में उतारचढ़ाव को रोकने के लिएनीति.निर्माताओं को पहले की अपेक्षा अधिक तरीके उपलब्ध हो गये हैं।

7) तटकर की संरचना का बहुत अधिक सीमा तक विवेकीकरण कर दिया गया है।तथा कर दरों एवं करों के माध्यम से एकत्रित धनराशि के बीच विपरीत संबंधआज वास्तविकता में घटित होते दिखायी दे रहे हैं।

8) पिछले 10 वर्षों में औद्योगिक संबंधों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। औद्योगिकविवाद
कम होकर लगभग 1/3 हो गये हैं तथा खोये गये श्रम दिवसों में 20प्रतिशत की कमी हो गयी है।

9) उच्च वृद्धि दरों ने सरकार के लिए आय में समृद्धि उत्पन्न की है। सरकार नेमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, भारत निर्माण, सर्वशिक्षाअभियान तथा

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 7, July - 2019
प्ैैछ;वद्धरू 2249.7382 द्य प्उचंबज थ्ंबजवतरू 6.939 द्य

International Journal of Research in Economics and Social Science (IJRESS)
Email:- editorijrim@gmail.com, http://www.euroasiapub.org
;।द वचमद ंबबमेे ेबीवसंतसलए चममत.तमअपमूमकए पदजमतकपेबपचसपदंतलए उवदजीसलए ंदक निससल तममितममक रवनतदंसण्द्ध

50

शिक्षा का अधिकार अधिनियम को सम्मिलित करते हुए बड़े सामाजिकप्रयास किया। अगला कार्यक्रम भोजन का अधिकार अधिनियम है जिसके अंतर्गतपरिवारों को 35 कि.ग्रा. प्रतिमाह अत्यधिक अनुदानित खाद्यान्न प्रदान किया जायगा।जनजातीय अधिकारों के लिए एक नया कानून लागू किया गया है किन्तु इसकापूर्ण क्रियान्वयन नहीं किया गया है।

इन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि आर्थिक सुधारों के परिणामस्वरूप मानसिकसोच में परिवर्तन आया है। एक उभरता हुआ नया मध्यम वर्ग अब उदारीकरण तथासुधारों के रथ का संचालन कर रहा है।ये सूचक अपेक्षाकृत कम समय में उल्लेखनीय हानि से लाभ में परिवर्तन सिद्ध करताहै। तथापि, ये सब हमें असफलताओं पर भी दृष्टिपात करने से नहीं रोकता है।

एक प्रारंभिक सुख का आभास होने के बाद ऐसा प्रतीत होने लगा कि सुधारों ने गतिखो दी है। भारतीय अर्थव्यवस्था के चारों ओर ’अविवेकपूर्ण बाहुल्य’ हो गया है। जिसप्रकार की वृद्धि विगत कुछ वर्षों में हमने देखी है वह एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करसकती है जिसमें लोग सोचते हैं कि यह हमेशा बनी रहेगी। विनियोग के अपेक्षाकृतऊँचे स्तर तथा विनियोग की उत्पादकता के बिना इन बातों के बने रहना कठिन है।और अधिक सुधारों क े बिना समावेशी बनाने में वृद्धि करना कठिन होता है। कुछमहत्त्वपूर्ण असफलताओं का उल्लेख नीचे किया जा सकता है।

1) नई आर्थिक नीति ने अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन उत्पन्ननहीं किया है जैसा कि विभिन्न सूचकों द्वारा संकेत किया गया है। प्रथम,औद्योगिक क्षेत्र का अंश वर्तमान म ें वही है जो यह 1989.90 में था। उससेपाँच वर्ष पूर्व की अवधि में इस अंश में निरंतर वृद्धि हुई है। द्वितीय, कृषि केअंश में कमी की गति सेवा क्षेत्र के द्वारा प्राप्त कर ली गयी है किंतु अर्थव्यवस्थामें सेवाओं के अपेक्षाकृत अधिक अंश ने सेवाओं की गुणवत्ता में कोई सुधार नहींकिया है। रोज़गार के अंश में अनुकूल परिवर्तन साधन होने पर सेवा क्षेत्र केपक्ष म ें भारतीय अर्थव्यवस्था के तीव्र संरचनात्मक संक्रमण का विस्तृत अभिप्रायइस वृद्धि ढाँचे की निरंतरता का ही नहीं बल्कि निर्धनता, असमानता एवं उत्पादकताके लिए भी होता है।

2) विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र के उदारीकरण एवं अर्थव्यवस्था को खोलने से संबंधितअच्छे/औसत के लंबे दौर के स्थिरकारी प्रभावों के बावजूद तथा उसकेविभिन्न संघटकों को सम्मिलित करते हुए बड़ी संख्या में महत्त्वपूर्ण समष्टिपरकआर्थिक चरों में अपेक्षाकृत अधिक उतार.चढ़ाव हुए हैं। इस प्रकार की प्रवृत्तियोंने अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक अनिश्चितता उत्पन्न की है जो दीर्घकालीन वृद्धि केअनुकूल नहीं होती है तथा आर्थिक अभिकर्ताओं को अधिक तरल रहने के लिएबाध्य करती है।भारत में न तो राजकोषीय और न

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 7, July - 2019
प्ैैछ;वद्धरू 2249.7382 द्य प्उचंबज थ्ंबजवतरू 6.939 द्य

International Journal of Research in Economics and Social Science (IJRESS)
Email:- editorijrim@gmail.com, http://www.euroasiapub.org (An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

51

ही मौद्रिक नीति व्यवसाय चक्र को स्थिरताप्रदान करती है। जिसके परिणामस्वरूप मंदी आने की स्थिति में भारत के लिएनीचे की ओर जोखित परिपक्व बाजार अर्थव्यवस्थाओं की अपेक्षा अधिक है।

3) कृषीय क्षेत्र का कार्य निष्पादन अल्प तथा मध्यम काल में लगभग बाह्यजनितदिये
होने तथा सेवा क्षेत्र की वृद्धि की स्वयं की गति होने से औद्योगिक क्षेत्रकी वृद्धि दर ही संपूर्ण ळक्च् की अपेक्षा अर्थव्यवस्था की प्रगति का एक बेहतरमाप है। सुधारों के पूर्व की अवधि की तुलना में सुधारों के पश्चात् की अवधिमें सभी क्षेत्रों में औद्योगिक कार्यनिष्पादन अपेक्षाकृत धीमा रहा है। इसके कमसे कम तीन पूरक कारण हैंः प्रथम, श्रम कानूनों के कारण उद्योग अपनी गतिविधियोंका निरंतर बाह्यस्रोतीकरण कर रहा है ताकि वास्तव में उद्योग में होने वालीवृद्धि की गणना सेवाओं में वृद्धि के रूप में की जाय। द्वितीय, श्रम कानून एवंऊर्जा क े क्षेत्रों में कुछ महत्त्वपूर्ण अनिवार्य सीमितताओं के कारण बड़ े पैमाने कीफर्में अब भी बाजार में प्रवेश करने की इच्छुक नहीं हैं।
References:
1द्ध क्ीपदहतंए प्ण् ब्ण् ;2012द्धरू ज्ीम प्दकपंद म्बवदवउलए ैनसजंद ब्ींदकए छमू क्मसीपए
2) OECD Economic Survey INDIA, June 2011, Academic Foundation, NewDelhi
3द्ध च्ंचवसंए ज्ण्ैण् ;2011द्धरू श्ैजतनबजनतम वf प्दकपंष्े म्बवदवउपब ळतवूजीरू ज्तमदके ंदकप्उचसपबंजपवदेरू कमसपअमतमक ंज प्ळछव्न्ण्
4द्ध च्संददपदह ब्वउउपेेपवदए ळवअमतदउमदज वf प्दकपंए म्समअमदजी थ्पअम लमंत चसंद ;2007.12द्ध प्दबसनेपअम ळतवूजीए टवसनउम प्ण्
5द्ध च्संददपदह ब्वउउपेेपवदए ळवअमतदउमदज वf प्दकपंए म्समअमदजी थ्पअम लमंत चसंद ;2007.12द्ध ैवबपंस ैमबजवतए टवसनउम प्प्ण्